आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, सोमवार 02 फरवरी 2026

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 83

■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

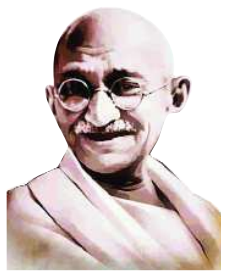

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

एजीएम में 600 प्रतिनिधि जुटे

पेज-2

लाइव परफॉर्मेंस से समां बांधेंगी मोनाली ठाकुर

पेज-5

नगर निगम का संपत्ति कर में घोटाला उजागर

पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- कर्नाटक : रमज़ान के महीने को देखते हुए उर्दू स्कूलों की टाइमिंग में किया गया अस्थायी बदलाव
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू
- पटना : बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा
- इस बार का बजट आत्मनिर्भरता वह दीपक है, जो आत्मसम्मान और सामर्थ्य का रास्ता दिखाता है : पीएम मोदी
- बजट सत्र : राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में करेंगे चर्चा की शुरुआत
- बिहार : आज से शुरू हो रही 12वीं की बोर्ड परीक्षा, बनाए गए हैं 1762 परीक्षा केंद्र
- जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता
- दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में छाया घना कोहरा
- दिल्ली : ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा
- पूर्वी डीआर कांगो में खदान ढहने से मरने वालों की संख्या 200 हुई
- हिमाचल प्रदेश : मनाली में फिर से हुई बर्फबारी
- सोने-चांदी में भारी गिरावट : सोना 1.39 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.49 लाख प्रति किलो पर पहुंची

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन के बीच चल रहा है अंतिम दौर का मंथन

दो हफ्ते में निगम-मंडलों के अंदर नियुक्तियों के आसार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● प्रदेश में निगम-मंडलों और विभिन्न प्राधिकरणों में लंबित पड़ी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन के बीच अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। मप्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले कुछ नियुक्तियों की सूची जारी हो सकती है। बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। इस तरह दो हफ्ते में नियुक्तियों की सूची जारी होने के आसार है। निगम-मंडलों में नियुक्ति की घोषणा एक साथ नहीं होगी। नियुक्तियों की घोषणा चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। सरकार और संगठन पिछले करीब चार महीनों से राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी में जुटा है। संगठन और सरकार स्तर पर कई दौर की चचर्चा के बाद सूची को लगभग अंतिम रूप भी दे दिया गया था, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। पहले योजना थी कि पहली किस्त में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों जैसे विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए अलग से सूची भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन उसे फिलहाल रोक दिया गया है।

पूर्व विधायकों और मंत्रियों के पुनर्वास पर फोकस- प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में लिया है। वे उपेक्षित और घर बैठ चुके वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहे है। इस बार की नियुक्तियों में पार्टी का खास फोकस पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों के पुनर्वास पर है। ऐसे कई नेता हैं, जो चुनाव के बाद संगठन या सरकार में किसी जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई नेताओं के पास फि लहाल कोई सक्रिय दायित्व नहीं है, जिसे देखते हुए पार्टी उन्हें निगम-मंडलों और आयोगों में समायोजित करना चाहती है।

तैयार हो रही पहली लिस्ट

राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची लगभग तैयार हो चुकी है। पहली सूची में विभिन्न निगम-मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों के पद भरे जा सकते है। दरअसल, विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से ही निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर संगठन पर दबाव बना हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव के बाद नियुक्तियां करने की योजना थी, लेकिन भाजपा के संगठन चुनाव, फिर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी के चलते मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद बिहार चुनाव के चलते भी निर्णय टलता रहा।

इस माह घोषित हो जाएंगी सभी जिला कार्यकारिणी

अगस्त में हुई थी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा 5 महीने बाद बनने लगी जिला कार्यकारिणी

भोपाल। मिशन-2028 की तैयारियों में जुटी मप्र कांग्रेस कमेटी ने लंबे इंतजार के बाद जिला कार्यकारिणी का गठन शुरू कर दिया है। पार्टी दो दिन में चार जिलों-सागर, छिदवाड़ा, मऊगंज व झाबुआ की कार्यकारिणी घोषित कर चुकी है। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। कोशिश है कि फरवरी अंत तक सभी 71 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाए। हालांकि यह किसी चुनौती से कम नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अधिकतर जिला कार्यकारिणी के नाम फाइनल हो गए हैं। उनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। कुछ जिलों की कार्यकारिणी के नामों पर मंथन चल रहा है। कार्यकारिणी के साथ ही पार्टी करीब 250 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी में है। अब तक 800 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। बता दे कि मप्र में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा अगस्त में हुई थी, लेकिन जिलाध्यक्ष बने पांच माह बीत जाने के बाद भी जिला कार्यकारिणी की घोषणा नहीं किए जाने से स्थानीय नेताओं में असंतोष पैदा होने लगा है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मंगलवार को संगठन के गठन में देरी को लेकर भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा था कि जितनी जल्दी संगठन मजबूत ढांचे में बदलेगा, उतनी ही बेहतर चुनावी तैयारी होगी। हम जितनी जल्दी संगठन बनाएंगे, उतनी ही मजबूती से चुनाव की तैयारी कर पाएंगे। इसकेतीन दिन बाद शुक्रवार को पीसीसी ने तीन जिला कार्यकारिणी और 18 जिला संगठन महासचिवों की घोषणा कर दी। गठन प्रक्रिया तेजी से जारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले का कहना है कि संगठन के गठन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नियुक्तियां की जा रही है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द संगठन के गठन का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि पूरी ताकत से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जा सके।

हितानंद शर्मा पर फैसले के बाद इंदौर में जुटे संघ के भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और सीएम

सत्ता, संगठन और संघ के लिए इंदौर दो दिन से बड़ी घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। शनिवार को संगठन महामंत्री पद से हितानंद शर्मा की विदाई की फैसला शनिवार को इंदौर में हुआ। वहीं रविवार को संघ के आला नेता भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, स्वप्निल कुलकर्णी, अरूण जैन के साथ ही सीएम डॉ. मोहन यादव भी इंदौर में थे। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की क्षेत्र कार्यकारिणी की शनिवार 31 जनवरी को हुई बैठक में संगठन महामंत्री पद से हितानंद शर्मा की विदाई की घोषणा हुई। इसके बाद संघ के बड़े नेता रविवार को भी इंदौर में रहे। एक कार्यक्रम में तो सीएम डॉ. मोहन यादव, वरिष्ठ प्रचार सुरेश सोनी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक साथ भोजन की टेबल पर भी नजर आए। इसमें क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी, अखिल भारतीय प्रचारक अरूण जैन भी रहे। वहीं एक कार्यक्रम में संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी भी थे।

सीएम के दौरे का सबसे अंतिम कार्यक्रम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ही विधानसभा एक में संगमनगर में था। यूथ विंग वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर सोनी और विजयवर्गीय साथ थे। सीएम कार्यक्रम में थोड़ी देरे से पहुंचे फिर सभी ने साथ में बैठकर भोजन किया।

संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिनकर राव सबनीस ने अपनाा पुश्तैनी मकान सोसायटी को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दिया है। डिप्टी एजी कुशल गोयल ने बताया कि सोसायटी यहां होस्टल, लाइब्रेरी और कम्पयूटर आदि की व्यवस्था करेगी। इसके लिए यहां चार मंजिला भवन बनेगा और इसके लिए भूमिपूजन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर सोनी ने कहा कि समाज के लिए यह सबसे बेहतर है कि हम संपत्तियों को समाज के उत्थान के लिए देकर जाएं। वहीं सीएम डॉ. मोहन यादव और मंत्री विजयवर्गीय ने भी इस कार्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम में सुरेश सोनी, कुलकर्णी, अरूण जैन, संघ से अभय महाजन, बिजनेसमैन नेहल, चिराग शाह, अनूप गोयल, अनिरूद्ध, अनूप गोयल के साथ सोसायटी के हरीश डागुर व अभय रांगणेकर व अन्य उपस्थित थे।

आंतरिक लड़ाइयों में उलझी मप्र कांग्रेस

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● एक तरफ कांग्रेस मप्र में सत्ता की वापसी की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता आंतरिक लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। आलम यह है कि मप्र कांग्रेस इस वक्त अव्यवस्था, अहंकार और असफल नेतृत्व की गंभीर स्थिति से गुजर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आलाकमान की बैठकों में भी बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, डा. विक्रांत भूरिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता अनुपस्थित रहे।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में गुटबाजी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि नेतृत्व का कोई भी निर्णय सर्वमान्य नहीं रह गया है। विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय पार्टी अपनी ही आंतरिक लड़ाइयों में उलझी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां नेतृत्व अहंकार से ग्रस्त हो, संगठन अनुशासनहीन हो और कार्यकर्ताओं में भ्रम हो- वहां रचनात्मक राजनीति संभव नहीं होती। ऐसे हालात में विपक्ष कमजोर होता है और लोकतांत्रिक संतुलन भी प्रभावित होता है। आज की स्थिति में मप्र कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक कलह और नेतृत्व संघर्ष के केंद्र के रूप में देखी जा रही है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। दरअसल, पार्टी में कई नेता उपेक्षित हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के पास प्रदेश के भीतर कोई काम नहीं है।

उन्हें संगठन सृजन के लिए अन्य प्रांतों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। यही कारण है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अजय सिंह हों या फिर डा. गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया या फिर अन्य नेता, अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं।

बड़े नेताओं की अनुपस्थिति पर उठे सवाल- दिल्ली बैठक में बड़े नेताओं की उनुपस्थिति को लेकर मीडिया ने जब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से सवाल किए तो वह असहज हुए और झल्लाते हुए बोले कि किसे बुलाना है और किसे नहीं, यह हमारा आंतरिक मामला है। इस पर प्रदेश भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि कमल नाथ बाहर, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे भीतर, यही कांग्रेस की हकीकत है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की बैठक के लिए केवल प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल को बुलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से संगठन सृजन अभियान और आगामी विधानसभा सत्र में पार्टी की भूमिका पर बात होनी थी, इसलिए केवल उससे जुड़े व्यक्तियों को बुलाया गया। दिग्विजय सिंह चूंकि प्रदेश में कांग्रेस के लिए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके संगठन को दे चुके हैं।

बसों के परमिट टैक्स में 50 फीसदी बढ़ोतरी से यात्राएं होगी महंगी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● प्रदेश में बस से यात्रा करने पर अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने बसों के परमिट टैक्स में 50 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। जिसका भार यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। शादी-विवाह और धार्मिक यात्राओं के लिए ज्यादा किराया चुकाना होगा। क्योंकि अस्थाई परमिट शुल्क 12 रुपए प्रति सीट से बढ़ाकर 18 रुपए कर दिया है। खास बात यह है कि अब बस कंडेक्टर (परिचालक) की सीट का भी टैक्स लिया जाएगा। जिसका भार भी यात्रियों पर पड़ेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बसों के स्थाई एवं अस्थाई परमिट शुल्क को बढ़ाने के संबंध में परिवहन विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को सूचना जारी की गई थी। जिसमें 65 फीसदी टैक्स बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन बस ऑपरेटरों के विरोध के चलते परिवहन विभाग ने 50 फीसदी परमिट शुल्क बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग की सूचना के बाद प्रदेश भर के कई बस ऑपरेटरों ने परमिट शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।

ये यात्राएं होंगी महंगी: यात्रा परमिट टैक्स बढ़ाने न सिर्फ सामान्य यात्राएं महंगी होंगी। बल्कि बारात, पिकनिक, धार्मिक, पिंडदान, अनुष्ठानों के लिए की जाने वाली यात्राएं भी महंगी हो जाएंगी। परिवहन विभाग बारात एवं अन्य यात्राओं के लिए अलग से परिमिट जारी करता है। टैक्स बढने पर आम लोगों पर ज्यादा बोझ आएगा। यूं तो यात्री बसों से प्रति सीट के हिसाब से टैक्स वसूली जाता है। शादी-विवाह एवं अन्य यात्राओं के लिए बसों को दिन के हिसाब से परमिट जारी होते हैं।

हर स्कूल पर रहेगी नजर, 700 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे प्रेक्षकों को

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● कक्षा 10वीं और 12वी की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं पर नजर रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा रिटायर्ड प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के साथ ही प्रिंसिपलों को भी प्रेक्षक की जिम्मेदारी दी जा रही है। इन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 700 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि हर स्कूल में विधिवत परीक्षाएं आयोजित हों और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल ही इसकी जानकारी मिले। बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए परीक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम बदलाव सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षकों की अनिवार्य तैनाती है। पिछले वर्ष जहां प्रेक्षक केवल संवेदनशील एवं अति संवेदनशील केंद्रों पर नियुक्त किए गए थे। वहीं इस बार मंडल द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। प्रेक्षक परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचेंगे और परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल समन्वयक केंद्र तक सुरक्षित पहुंचने तक केंद्र पर मौजूद रहेंगे। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल खुलवाने, उनका सुरक्षित वितरण, परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और उत्तर पुस्तिकाओं को जमा कराने तक की पूरी प्रक्रिया प्रेक्षकों की निगरानी में होगी।

तैयारी सार्वजनिक परिवहन और आवागमन की सुविधा भी होगी बेहतर, परेशान नहीं होंगे चालक

इस साल शहर में मिलेंगे 10 नए ब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में इस साल ट्रैफिक की परेशानी कम होने की उम्मीद है। इस साल 10 नए ब्रिज और फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर वाहन आवागमन सुगम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम में काफी हद तक कमी आएगी। इन 10 ब्रिजों और फ्लाईओवर में से कुछ का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और कुछ पर अंतिम चरण में काम चल रहा है। लंबे समय से इन स्थानों पर ब्रिज की मांग हो रही थी। मांगलिया, बाणगंगा, शक्कर खेड़ी और पोलो ग्राउंड पर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर तैयार किए जाएंगे। चारों स्थानों पर ब्रिज बनने से जिले में रेलवे गेट पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा।

गेट इतिहास बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा मूसाखेड़ी, देवास नाका, अर्जुन बड़ौदा, सत्यसाईं चौराहा, रेती मंडी और बेस्ट प्राइस के पास भी फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। यह काम एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग कर रहे हैं।

वैकल्पिक मार्ग से ट्रैफिक : फुटपाथ और जल निकासी की सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है, साथ ही निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने वैकल्पिक मार्गों और संकेतों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। शहरवासियों का कहना है कि लंबे समय से ट्रैफिक जाम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी का कारण बन रहा था। नए ब्रिज और फ्लाईओवर बनने के बाद न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन और आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी।

पीक अवर्स में नहीं लगेगा जाम

इन स्थानों पर सुबह और शाम के पीक अवर्स में वाहनों की भारी भीड़ रहती है और फ्लाईओवर बनने के बाद इन इलाकों में यातायात सुचारू रूप से चलेगा। वाहन चालकों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करना और लोगों की यात्रा को आसान बनाना है। अधिकारियों की मानें तो नए ब्रिज और फ्लाईओवर आधुनिक तकनीक और संरचना के अनुसार बनाए जा रहे हैं, जिससे उनकी क्षमता और मजबूती लंबे समय तक बनी रहे।

न्यूज ब्रीफ

दूसरी कक्षा की छात्रा को किया बेड टच, पुलिस को सौंपा आरोपी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कचरा फेंककर लिफ्ट से अपने घर जा रही दूसरी कक्षा की छात्रा को युवक ने बेड टच किया। छात्रा की शिकायत पर परिजन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाणगंगा पुलिस को फरियादी ने बताया कि मैं टी मर्चेन्ट एसोसिएशन स्कूल से कक्षा दूसरी की छात्रा हूं। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं होने से 3-4 दिन से तुलसीयाना चंदन होम्स में नानी के घर आई हूं। 31 जनवरी को दोपहर ढाई बजे कचरा डालने बी ब्लॉक की लिफ्ट के नीचे गई थी। कचरा डालकर जब वापस लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, तभी लिफ्ट के अंदर खड़े भैया, जिन्हें मैं नहीं जानती, मुझे धक्का देने लगे। ऐसा उन्होंने तीन-चार बार किया। मैं घबराकर लिफ्ट से बाहर निकली और सारी बातें अपनी मौसी को बताईं। मौसी ने लिफ्ट में खड़े युवक सुमित पिता मुकेश बंसल निवासी परदेशीपुरा को पकड़ा और मौके पर सबक सिखाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया।

विषय : विहिप-बजरंग दल द्वारा गुरु रविदास जयंती पर किया माल्यार्पण

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मालवा मिल, रुस्तम का बगीचा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भक्ति एवं सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रचार प्रमुख श्री अन्नू गेहलोत ने बताया कि संत रविदास जी ने अपने जीवन में जाति-भेद, छुआछूत एवं सामाजिक असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और समतामूलक समाज का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्य प्रांत प्रचार प्रमुख श्री गन्नी चौकसे ने अपने उद्बोधन में कहा कि संत रविदास जी के विचार आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं और उनके आदर्श हमें सामाजिक एकता एवं समरसता की प्रेरणा देते हैं। विभाग मंत्री श्री यज्ञेश राठी ने कहा कि संत रविदास जी का सपना ऐसा समाज था जहाँ सभी को समान अधिकार, सम्मान एवं अवसर प्राप्त हों।

अग्रवाल समाज का तीन दिवसीय निशुल्क परिचय सम्मेलन 28 मार्च को गांधी हाल में

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● ब्रह्मलीन समाजसेवी मिश्रीलाल गोयल की पुण्य स्मृति में श्री अग्रवाल महासभा की मेजबानी में शनिवार 28 मार्च से सोमवार 30 मार्च तक गांधी हॉल परिसर में तीन दिवसीय नि:शुल्क 33वां अ.भा. युवक-युवती परिचय सम्मेलन के लिए देश के 100 से अधिक शहरों में प्रविष्ठि पत्र पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। हिंदी भाषी राज्यों में इस बार 100 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष होने वाले इस निशुल्क अ.भा. परिचय सम्मेलन में 2 हजार से अधिक प्रविष्ठियां मिलने का कीर्तिमान पिछले 2 वर्षों से बन रहा है। महासभा के समन्वयक संतोष गोयल, अध्यक्ष सतीश गोयल एवं महामंत्री अजय बंसल ने बताया कि परिचय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज यशवंत निवास रोड स्थित महासभा के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में समाज बन्धु शामिल हुए।

रियलमी ने पेश किया रियलमी पी4 पॉवर 5जी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भारत में युवाओं के सबसे अधिक लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड, रियलमी ने आज रियलमी पी4 पॉवर 5जी पेश किया। यह स्मार्टफोन बैटरी इनोवेशन को एक नए आयाम में ले गया है। एक बड़ी टेक्नोलॉजी प्रगति के साथ इसमें उद्योग की पहली 10,000 एम.ए.एच से अधिक क्षमता की बैटरी दी गई है। इसलिए रियलमी पी4 पॉवर 5जी भारत की पहली 10,001 एम.ए.एच क्षमता की बैटरी के साथ एंड्योरेंस के मामले में नए मानक स्थापित कर रहा है।

यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा - मुख्यमंत्री

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्री तुलसीराम सिलावट, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, विधायक मालिनी गौड, महेंद्र हार्डिया, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम अध्यक्ष सावन सोनकर, सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगवान परमार, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा की उपस्थिति में डेली कॉलेज के डीसीबीएम हॉल में प्रबुद्धजनों के साथ केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026 - 27 का लाइव प्रसारण देखा और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप है। यह बजट आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। बजट में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में रिफार्म के प्रावधानों से मध्यप्रदेश के कपड़ा उद्योग को बहुत फायदा मिलेगा। बजट में राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ के अनुदान का प्रावधान मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के विकास में बड़ा सहायक होगा। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को

वैश्विक स्तर पर और उच्च स्थान पर पहुंचाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.3 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। भारत को बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का भी विकास होगा। केंद्रीय बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारियों की दवाऐं भी सस्ती होंगी, जिससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है, इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी विशेष लाभ होगा।

सीवेज के काम में लापरवाही करने वाली कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्ट- आयुक्त

शहरों में सीवेज और पानी की पाइप लाइन एक साथ नहीं मिलाई जाए

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) के एमडी संकेत भोंडवे ने रविवार को पूर्ण हो चुकी प्रदेश के 35 नगरीय निकायों एवं प्रगतिरत 52 नगरीय निकायों की जलप्रदाय एवं सीवेज योजनाओं की समीक्षा की।

उन्होंने काम में लापरवाही और कार्य की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर बुधनी तथा सांची शहर सहित अन्य शहरों के आधा दर्जन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने, रजिस्ट्रेशन निरस्त करने और सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इंजीनियरों और ठेकेदारों से कहा है कि सीवेज और पानी की पाइप लाइन डालते समय यह ध्यान दें कि ये दोनों लाइनें आपस में न जुड़ें। उन्होंने विशेष रूप से सड़क रोड रेस्टोरेशन कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने पर जोर दिया। भोंडवे ने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष परियोजनाओं में आ रही अतिक्रमण या अन्य बाधाओं को रखा जाए, ताकि समय पर समाधान किया जा सके। जल परीक्षण के लिए एमपीयूडीसी के माध्यम से 10 हजार महिला अमृतमित्र तैनात किए जाएं।

इन पर कार्रवाई के निर्देश-एकीकृत विकास परियोजना बुधनी के ठेकेदार वाज इंडिया को टर्मिनेट करने एवं ब्लैक लिस्ट करने, पसान के मुख्य ठेकेदार द्वारा नियुक्त सब कांट्रेक्टर कात्यानी, शहडोल सीवरेज में मुख्य ठेकेदार द्वारा नियुक्त सब कांट्रेक्टर ईफिल तथा सांची सीवरेज परियोजना के ठेकेदार 3 आर एम को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश भी प्रबंध संचालक द्वारा दिए गए। ईपीसीएल को टर्मिनेट करने की चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

फिर से याद किए वो आफिस के दिन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एक आफिस ही वो जगह होती है जहां हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। वहां हम सीखते भी है सिखाते भी है। सीनियर की डांट खाते है और टीम को संभालते भी है। लेकिन जब हम उस संस्था से विदा होते है तो सारी यादे धीरे धीरे भूल जाते है। उन्ही यादों को फिर से जीने पहली बार किसी संस्था के कर्मचारियों की रियूनियन हुई।

मालवा कालेज के स्टॉफ ने एक गेट टुगेदर पार्टी आयोजित की थी। शंकर रघुवंशी ने बताया कि छात्र छात्राओं की रियूनियन तो आम बात है किंतु किसी कॉलेज या आफिस के स्टाफ का फिर से मिलना बड़ी बात है। इस पार्टी के लिए शालिनी दुबे हैदराबाद और जयराज पुणे से विशेष रूप से आये थे। कार्यक्रम में आते ही जब आपस में मिले तो आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे इतने दिनों की दूरी जैसे गायब ही हो गई थी। मनीष चौधरी ने कहा कि वहां से नोकरी छोड़े 10 साल से ज्यादा हो गए लेकिन आज भी उन सभी साथियों से अपनापन बरकरार है। पार्टी में मनोरंजक गेम्स डॉ सरबजीत ने खिलाये, मोहनीश ने स्टाफ की मिमक्री कर खूब हंसाया। दीपा नैयर और मोनी सकारिया ने गिफ्ट्स बांटे। पवित्रा शर्मा और दिव्या गुप्ता को बेस्ट ड्रेस अवार्ड भी दिया गया। परितोष शांडिल्य ने सारे आयोजन की व्यवस्था की। संचालन महेश मकवाना ने किया। आभार विजेंद्र सोगानी ने माना।

लोगों में तेजी से कमी हो रही है विटामिन-डी की

वर्क फ्रॉम होम और एसी लाइफ स्टाइल बनी बड़ी वजह

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर में विटामिन डी की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रही है। हाल ही के 9 हजार से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण में यह सामने आया है कि शहर में महिलाओं और पुरुषों दोनों में 36 से 37% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं।

एक्सपर्ट्स ने इस पर चिंता जताई है। डॉक्टरों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह बदलती लाइफ स्टाइल, वर्क फ्रॉम होम कल्चर और एयर कंडीशनिंग वाले बंद माहौल में अधिक समय बिताना है। ऐसे माहौल में लोगों को पर्याप्त धूप नहीं मिल पा रही है।

यह जानकारी कोकिलाबेन धीरुबाई अंबानी हॉस्पिटल की सालाना हेल्थ स्टडी में सामने आई है। इनमें 3454 महिलाओं और 5964 पुरुषों को आयु वर्ग में बांटा गया। एक 45 वर्ष से कम उम्र और दूसरा 45 वर्ष या उससे ज्यादा। इसमें पाया गया कि 36.30% पुरुषों और 37.30% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है जो अधिक उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा थी। रिपोर्ट के अनुसार- 3454 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 1288 महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई। इसी तरह 5964 पुरुषों के परीक्षण में 2164 पुरुषों में विटामिन डी की कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 37 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है।

कंसलटेंट क्लालिटी चीफ डॉ. गौरव शैलगांवकर का कहना है कि मानव शरीर मूल रूप से खुले वातावरण में काम करने के लिए बना है। पहले लोग खेती, श्रम और आउटडोर गतिविधियों से जुड़े रहते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग कॉर्पोरेट और केबिन आधारित नौकरियों में काम कर रहे हैं।

लंबे समय तक बंद कमरों में रहने और एसी वातावरण में काम करने से शरीर को प्राकृतिक धूप नहीं मिल पाती, जिससे विटामिन डी का स्तर गिर रहा है।

बच्चों में भी बढ़ रही समस्या

डॉक्टरों ने चिंता जताई कि अब यह समस्या केवल वयस्कों तक सीमित नहीं रही। पहले बच्चे क्रिकेट, कबड्डी और अन्य आउटडोर खेलों में सक्रिय रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और इनडोर गतिविधियों में अधिक समय बिताने के कारण बच्चों में भी विटामिन डी की कमी के मामले सामने आ रहे हैं।

हड्डियों से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक असर

एक्सपर्टस के अनुसार विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और बार-बार फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा विटामिन डी बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और इसकी कमी से डिप्रेशन, थकान और चिड़चिड़ापन भी देखा गया है। खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में शरीर को अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है।

श्री विश्वकर्मा प्रकटोत्सव सम्पन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्री विश्वकर्मा प्रकटोत्सव के अवसर पर श्री विश्वकर्मा पांचाल समाज इन्दौर बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री विश्वकर्मा प्रकटोत्सव पांचाल धर्मशाला भवन, सूर्यदेव नगर, इन्दौर पर मनाई गई। इस अवसर पर प्रात: भगवान श्री विश्वकर्मा का श्रृंगार, पूजन एवं महाआरती कर रथ यात्रा का निकाली गई जिसमें पांचाल समाज के महिला-पुरूषों द्वारा रथ खेचा गया। यात्रा मार्ग में समाज बंधुओं द्वारा जगह-जगह स्वागत मंच लगाकर भगवान श्री विश्वकर्मा का स्वागत किया गया। समाज के मनोज नंदकिशोर पांचाल ने बताया कि इस अवसर पर रथ यात्रा पश्चात भगवान श्री विश्वकर्मा का आकर्षक श्रृंगार कर शाम को महाप्रसादी का वितरण भी किया गया।

ग्राइंडर से कटकर लटक गई थी गर्दन एमवाय के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एमवाय अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 38 वर्षीय युवक की सर्जरी की। घर पर लोहे की रॉड काटते समय उसकी गर्दन कटकर लटक गई। खाने की और सांस नली दोनों कट गई और खून भी ज्यादा बह गया, लेकिन एमवाय के डॉक्टरों ने इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया और युवक की जान बचा ली। इस हादसे के बाद उसकी आवाज जाने का भी खतरा था, लेकिन वह भी ठीक कर दी गई। अस्पताल में 17 जनवरी की शाम को सोहन पिता पन्नालाल निवासी गोकुल नगर आया था। परिजनों ने बताया कि उसकी गर्दन ग्राइंडर से कट गई। घाव इतना बड़ा था कि सिर के अंदर की नसें दिख रही थीं। तत्काल उसकी सर्जरी का फैसला लिया गया और डॉक्टर सुदर्शन ओडिया, डॉ. संजय महाजन, शुभ घनघोरिया व अन्य डॉक्टरों ने उसकी कटी सांस नली और आहार नली जोड़ दी।

छत पर करीब एक घंटे नाबालिग के साथ रहा हत्यारा, साथी की तलाश में पुलिस

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एमआईजी थाना इलाके में एक नाबालिग की युवक ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बाद में शव को फ्लैट में पलंग पेटी में छिपा दिया था। पुलिस ने शंका के आधार पर नाबालिग के हत्यारे को पकड़ लिया। उसके एक साथी की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि वह दोनों करीब एक घंटे से ज्यादा देर तक छत पर थे। मामला इंदौर के श्रीनगर इलाके का है। यहां रहने वाले 13 साल के नाबालिग की रेहान ने हत्या कर दी थी। एमआईजी थाना प्रभारी सी.बी.सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ही नाबालिग को इशारा कर बुलाया था। जिसके बाद वह उसे छत पर ले गया और वहां पर उसके साथ हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने पर उसने नाबालिग को ईंट मारी और रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। नाबालिग के लापता होने पर परिवार के लोग उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। शुक्रवार देर रात को परिवार के लोगों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

विनय बाकलीवाल विवाद : एजीएम में 600 प्रतिनिधि जुटे, बिना चुनाव बने अध्यक्ष को नकारा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● दिगम्बर जैन समाज (सामाजिक संसद), इंदौर में अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा संवैधानिक विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। समाज की साधारण सभा (एजीएम) में 85 से अधिक जैन मंदिरों के करीब 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा में बिना चुनाव अध्यक्ष बनाए जाने की कड़ी निंदा की गई, वोटर लिस्ट अपडेट करने और संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।

दिगम्बर जैन समाज (सामाजिक संसद), इंदौर की साधारण सभा (AGM) में समाज का स्पष्ट संदेश सामने आया- अध्यक्ष वही होगा, जो संविधान और चुनाव से आएगा। यानी पूर्व में अध्यक्ष घोषित हुए विनय बाकलीवाल को किसी ने भी अपना अध्यक्ष नहीं माना।

सभा में इंदौर के 85 से अधिक जैन मंदिरों के मंत्री, अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। कुल उपस्थिति 550 से 600 सदस्यों के बीच रही। सभी प्रतिनिधियों का विधिवत रजिस्ट्रेशन किया गया। किसी भी स्तर पर कोई विरोध या आपत्ति दर्ज नहीं हुई। सभा के दौरान पूर्व में संविधान के विरुद्ध जाकर अध्यक्ष घोषित किए जाने की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

दरअसल समाज में दो अध्यक्ष होने से बदनामी बढ़ने लगी थी एक गुट के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी दूसरे गुट के अध्यक्ष नरेंद्र

वेद थे। इसी को ध्यान में रख कर दो वर्ष पहले मुनि सागर जी के इंदौर आगमन पर दोनों गुटों के अध्यक्षों से निवेदन किया गया था आप दोनों इस्तीफा दो।

इसके बाद समाज के संविधान से एक चुनाव हो और एक अध्यक्ष चुना जाए। इस क्रम ने नरेंद्र वेद ने तो इस्तीफा दे दिया था वहीं राजकुमार पाटोदी ने बोला था कि मेरे जितने भी पदाधिकारी है उनसे बातचीत करूंगा।

इस पर एक मीटिंग हुई जिसमें 69 प्रतिनिधि उसमे सम्मिलित हुए। यहां तय हुए की नामांकन और चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि एक नाम आता है तो निर्विरोध अध्यक्ष होगा वहीं अधिक नाम आते है तो चुनाव होगा। जो जीतेगा वो समाज का अध्यक्ष होगा। इस पर एक समन्वय समिति बनी जिसके मुख्य समन्वयक विनय बाकलीवाल थे। वह बिना किसी संविधान की प्रक्रिया को फॉलो किए बिना अध्यक्ष बन गए। इसी को लेकर सामाज में आक्रोश था । 'हमारी आपत्ति व्यक्ति से नहीं है। आपत्ति सिर्फ इतनी है कि बिना चुनाव, बिना संविधान कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता।

विनय बाकलीवाल को अध्यक्ष मानने से इंकार

AGM में मौजूद प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा आज मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र जैन (रिटायर्ड जज) की घोषणा की गई। वहीं उन्हीं के साथ चार लोगो की कमेटी बनाई गई । जिसमे प्रिंसिपल टोंग्या , डी.के. कुमार जैन (पूर्व DSP), कुशलराज जैन, राजू अलबेला शामिल हैं । समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पूरी प्रक्रिया संविधान और पारदर्शिता के अनुसार हो । इस कारण विनय बाकलीवाल को अध्यक्ष मानने से समाज ने औपचारिक रूप से इंकार कर दिया । उल्लेखनीय है कि उनसे विनय बाकलीवाल स्वयं उपस्थित नहीं थे । दिगम्बर जैन समाज का संविधान अध्यक्ष को अपार अधिकार देता है । अगर अध्यक्ष चुनाव के बिना बना, तो भविष्य में—संविधान निष्प्रभावी होगा । समाज में स्थायी विभाजन बनेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी । इसी कारण विरोध व्यक्ति से ज्यादा प्रक्रिया को लेकर है ।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, सोमवार 02 फरवरी 2026

तीन लाख शिक्षकों की स्थानांतरण नीति अभी भी अधर में

भोपाल (एजेंसी) ●मप्र में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने वाली है। लेकिन विडंबना यह है कि करीब चार साल पहले जिस नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, वह लागू तो हो गई है, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी में एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट करने की बात कही गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है। इसमें तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और आदेश भी ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि तत्कालीन शिवराज कैबिनेट ने 2 अगस्त, 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी थी। ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिले चार साल होने को हैं, लेकिन अब तक सरकार एक बार भी इस पर अमल नहीं कर पाई है। ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए प्रावधान के अनुसार हर साल शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को 15 मई तक नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। पॉलिसी लागू होने के बाद एक बार भी इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। इस साल भी अब तक स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने पोर्टल चालू नहीं कर पाया है। प्रदेश के स्कूलों में करीब 3 लाख शिक्षक पदस्थ हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में तीन साल नौकरी करना अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम तीन साल नौकरी करना अनिवार्य होगा। उन्हें वचन पत्र भी देना होगा। शिक्षकों को अपने पूरे सेवाकाल में 10 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना होंगी। शहरी क्षेत्रों में 10 साल तक पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर तीन साल से पहले उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा, जहां तबादला किया गया है। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूल में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। इसमें दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ शिक्षकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने और शिक्षक व प्रिंसिपल को मंत्रियों, विधायकों या अन्य जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किए जाने का प्रावधान गया है। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार, तीन साल में सेवानिवृत्त होने वाले गंभीर बीमार या विकलांग और एक साल से कम की सेवा एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता होने पर तबादला नहीं किया जाएगा। दूसरे विभागों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। रिलीव करने और जॉइन करने की कार्रवाई ऑनलाइन होंगी।

जल्द चालू होंगे पोर्टल

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कोशिश है कि ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने पोर्टल जल्द चालू कर दिया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार, नए स्कूल अथवा संकाय के शुरू होने पर सेट अप में संशोधन 31 दिसंबर तक किया जाएगा। एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट की जाएगी। रिक्त पदों का निर्धारण 31 जनवरी तक किया जाएगा। रिक्त पदों की जानकारी एमपी एजुकेशन पोर्टल पर 1 मार्च तक अपलोड की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च होगी। 30 अप्रैल तक तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षकों को नए कार्यस्थल पर 15 मई तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।मध्य प्रदेश व्यापार निर्देशिका

भोपाल की ताल के चौपाल से

कप्तान साहब की धुआंधार बल्लेबाजी, मामा का मैजिक शॉट और पंडित जी प्लेइंग इलेवन से बाहर

बोल हरि बोल

हरीश दिवेकर

मध्यप्रदेश की सियासी पिच पर क्रिकेट के रंग दिख रहे हैं। कप्तान साहब की धुआंधार बल्लेबाजी, मामा का मैजिक शॉट, और कलेक्टर साहब का विवादित व्यवहार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज के बोल हरि बोल में पढ़िए इन घटनाओं के बारे में विस्तार से... क्रिकेट के मैदानों में चौकों-छक्कों की बरसात चल रही है। जमीन पर मावठा मेहरबान है। वहीं मध्यप्रदेश की सियासी और अफसरशाही की पिच पर हर खिलाड़ी अपनी-अपनी स्टाइल में खेल रहा है। हर कोई अपनी पारी लंबी करने की जुगत में है। कोयलांचल वाले जिले के कप्तान साहब की बल्लेबाजी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनकी पारी इतनी तेज है कि इसकी खबर सीधे थर्ड अंपायर यानी पीएचक्यू तक पहुंच चुकी है। अब आगे नो बॉल होगी, फ्री हिट मिलेगा या विकेट गिरेगा, इस पर सबकी नजर है। उधर, दाढ़ी वाले साहब बैठकों में धुआंधार कमेंट्री कर रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी को सीधे सवालों के बाउंसर फेंक देते हैं। दिलचस्प यह है कि उनके कैप्टन भी पूरा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सियासी पिच पर एक बड़ा बदलाव भी हुआ है। पंडित जी अब प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं। यह स्ट्रैटेजिक रेस्ट है या टीम कॉम्बिनेशन का खेल, इस पर सियासी कमेंटेटर अपने-अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। बाकी टूर्नामेंट लंबा है। मैच भी बचे हैं और खिलाड़ी भी।

क्या राजनीति में जाएंगे साहब!

बड़वानी के लोगों ने हाल ही में एक ऐसा जुलूस देखा है, जिसने थोड़ी देर के लिए उन्हें कन्फ्यूज कर दिया। कई लोगों को लगा कि कोई बड़ा नेता चुनाव जीत गया है। किसी को लगा कि कोई नया नेता लॉन्च हो रहा है। बाद में सामने आया कि मामला कुछ और ही था। दरअसल, यह आयोजन एसपी रहे जगदीश डावर की विदाई का था। शहर में बैनर और पोस्टर लगाए गए। स्वागत के इंतजाम भी तगड़े थे। डावर साहब खुली जीप में सवार थे। स्टाइल बिल्कुल वैसी थी, जैसी आम तौर पर चुनावी रोड शो में दिखाई देती है। लोग सड़क किनारे खड़े होकर हाथ हिला रहे थे और एसपी साहब अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जुलूस के आगे डीजे बज रहा था। लोग नाचते-गाते साथ चल रहे थे। यह नजारा जिसने भी देखा, उसे लगा कि यह सामान्य विदाई कार्यक्रम से थोड़ा ज्यादा है। अब चर्चा है कि यह सिर्फ विदाई नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। डावर साहब का परिवार राजनीति से जुड़ा है। डावर साहब खुद भी बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका अगला कदम राजनीति की तरफ हो सकता है।

मामा का एक और मैजिक मॉडल

सूबे की सियासत में अगर किसी नेता की स्टाइल अलग पहचान रखती है तो उसमें मामा का नाम सबसे ऊपर आता है। मंच हो, सभा हो या सरकारी कार्यक्रम मामा का अंदाज हमेशा हटकर रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मंच से मुस्कुराते हुए मामा ने कहा कि उनके क्षेत्र विदिशा-रायसेन के जो बच्चे 10वीं और 12वीं में शानदार नंबर लाएंगे, उन्हें प्रेम-सुंदर सम्मान दिया जाएगा। यानी पढ़ाई में अच्छा करो और मामा से सम्मान पाओ। यह योजना इसी साल के बोर्ड रिजल्ट से लागू होगी। अब राजनीतिक गलियारों में इस घोषणा की अलग-अलग तरह से चर्चा हो रही है। समर्थक कह रहे हैं कि मामा हमेशा बच्चों और युवाओं के लिए कुछ नया सोचते हैं। दूसरी तरफ विरोधी खेमे में कानाफूसी तेज हो गई है। कुछ लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मामा अपने संसदीय क्षेत्र में इतना एक्टिव रहते हैं कि लगता है मानो वहां अलग ही प्रशासनिक मॉडल चल रहा हो। फिलहाल इतना तय है कि मामा अपने अंदाज से सुर्खियां बटोरना जानते हैं। कभी योजनाओं से, कभी भाषणों से और कभी अचानक किए गए ऐलानों से।

कलेक्टर साहब का व्यवहार...हाय राम?

महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे एक जिले के कलेक्टर साहब इन दिनों अपने काम से ज्यादा अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में हैं। अंदरखाने बात चल रही है कि साहब मीटिंग और दफ्तर में अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहद सख्त और कई बार मर्यादा से बाहर भाषा में बात करते हैं। पिछले दिनों तो एक अधिकारी दफ्तर से आंसू पोंछते हुए बाहर निकला था। अब एक और मामला सामने आया है। कलेक्टर साहब एक लिपिक पर भड़क पड़े। उसे अपशब्द तक कह डाले। बोले, 'ह**मी... शिकायतें पेंडिंग हैं, कुछ नहीं करता, ऊपर बैठा रहता है, कोई काम नहीं है। इसे नीचे लाकर बैठाओ। 'इसके बाद अपने स्टेनों पर भी असभ्य तरीके से भड़के। जब कलेक्टर यह डायलॉग डिलेवरी कर रहे थे, तब वहां कुछ मीडियाकर्मी भी थे। साहब की शिकायतें अब ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह है कि यह चर्चा फाइलों तक सीमित रहती है या आगे कोई औपचारिक कार्रवाई का रास्ता बनता है।

कोयलांचल के करोड़ीमल कप्तान!

कोयला दिखने में भला काला होता है, लेकिन हर कोई इसके रंग का कायल होता है। अब देखिए न, मध्यप्रदेश में भी खूब कोयला होता है। ऐसे ही कोयला पैदा करने वाले एक जिले के पुलिस कप्तान साहब इन दिनों चर्चाओं में हैं। वैसे तो यह जिला बैठे बिठाए चंद अफसरों को गांधी जी के दर्शन कराता ही है, लेकिन कप्तान साहब 'करोड़ीमल' बन गए हैं। जी हां, सही पढ़ा है आपने 'करोड़ीमल'। दरअसल, कप्तान साहब ने जिले के सात थानों की बंदी बांध दी है। इन थानेदारों की जिम्मेदारी है कि हर महीने एक खोका साहब तक पहुंचाया जाए, बस फिर क्या है...कप्तान साहब कहें और थानेदार काम न करें, ऐसा हो सकता है क्या भला? खूब माल पीटा जा रहा है। कोयले की दलाली के सबके हाथ काले हो रहे हैं। साहब के इस कांड की भनक पीएचक्यू तक पहुंच गई है। दिलचस्प यह है कि कुछ बड़े अफसरों को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन उनकी मेहरबानी बरकरार है?

दाढ़ी वाले बाबा का खौफ...

अफसरशाही में फिलवक्त दाढ़ी वाले बाबा का नाम खूब चर्चित है। अफसरों में बड़े साहब का जितना डर है, उससे कहीं ज्यादा घबराहट बाबा की मौजूदगी से होने लगी है। बैठकों में बाबा का अंदाज अलग ही रहता है। वे सीधे मुद्दे पर आते हैं और कई बार किसी भी अफसर की जमकर क्लास लगा देते हैं। ऐसे मौकों पर बड़े साहब रोकने या माहौल हल्का करने की जगह बाबा का समर्थन करते दिखते हैं। इससे सिस्टम में साफ मैसेज जा रहा है कि बाबा की बात को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से अब अफसरों के बीच बाबा का खौफ बढ़ता जा रहा है। अंदरखाने यह भी चर्चा है कि कई अफसर बैठकों से पहले ही होमवर्क करके पहुंचते हैं, ताकि कहीं बाबा के निशाने पर न आ जाएं। मजेदार किस्सा यह भी चल रहा है कि अफसर आपस में आधे मजाक और आधे डर में यही कामना कर रहे हैं कि बाबा कुछ समय आध्यात्मिक साधना या विपश्यना कैंप चले जाएं, ताकि सिस्टम में थोड़ी राहत मिल सके।

तुम रूठे और हम छूटे!

सिस्टम में इन दिनों नई गॉसिप चल रही है कि दिल्ली वाला रास्ता अब सेफ ऑप्शन बन गया है। इसके पीछे वजह ड्डत पद के इम्पैनलमेंट को लेकर आया नया नियम है। इस नए नियम में एसपी और डीआईजी रैंक के अफसरों के लिए कम से कम दो साल का केंद्र डेपुटेशन जरूरी कर दिया गया है। अंदरखाने कई अफसर इसे अपने लिए सेफ्टी वॉल्व मान रहे हैं। बात चल रही है कि यदि कभी राज्य सरकार से रिश्ते बिगड़ गए या मनमुताबिक पोस्टिंग नहीं मिली तो अफसर सीधे दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेंगे। मतलब साफ है कि अब लूप लाइन में बैठकर सालों तक इंतजार करने का डर पहले जैसा नहीं रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अफसर पहले ही अपने दिल्ली कनेक्शन मजबूत करने में जुट गए हैं, क्योंकि यदि राज्य नाराज हुआ तो दिल्ली दूर नहीं है। अब यह नया सिस्टम राज्य और अफसरों के रिश्तों को कितना बदलता है, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल तो खाकी के कॉरिडोर में यही लाइन सबसे ज्यादा घूम रही है कि तुम रूठे और हम छूटे।

पंडित जी की 'घर वापसी'

लंबे समय तक सत्तारूढ़ खेमे का मैनेजमेंट संभालने के बाद आखिरकार पंडित जी की संघ में वापसी हो गई है। भोपाल में मजबूत पकड़ बनाने वाले पंडित जी को अब जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला अचानक नहीं, बल्कि लंबे मंथन के बाद लिया गया है। कुछ समय से इस पर लगातार बातचीत चल रही थी। अब पंडित जी को इंदौर मुख्यालय बुलाकर औपचारिक रूप से नई जिम्मेदारी की जानकारी दी गई। वहां संगठन के बड़े नेताओं के साथ उनकी लंबी बैठक हुई, जिसके बाद तस्वीर साफ हो गई। अब राजनीतिक हलकों में इसे बड़े संगठनात्मक संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। भोपाल से जबलपुर शिफ्ट होने को कुछ लोग नई रणनीति बता रहे हैं तो कुछ इसे बड़े फेरबदल की शुरुआत मान रहे हैं। फिलहाल नए मुखिया का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ प्रचारक को नई जिम्मेदारी मिलेगी।

केंद्रीय बजट से देश के कर्मचारी निराश : दिनेश परमार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भारत सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए निराशजनक रहा। जहाँ सरकार इस बजट को भविष्य का बजट कह रही है, परन्तु कर्मचारियों के भविष्य के लिए सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) के जिलाध्यक्ष एवं शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश परमार ने बताया कि सबसे बड़ी बात देश के एक करोड़ से अधिक शासकीय अधिकारी कर्मचारी एवं अर्द्धसैनिक बलों के जवान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की अगुवाई में आंदोलन कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहें है। सरकार ने इसे पूरी तरह अनदेखा किया है। परमार ने बताया कि संसार की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है कर्मचारियों सहित देश की सीमा सुरक्षा में लगे हुए अर्द्ध सैनिक बलों को नजर अंदाज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

भाजपा का जिला ग्रामीण का जिला सम्मेलन संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● 'विकसित-भारत जी राम जी' गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिला ग्रामीण का जिला सम्मेलन शनिवार को सर्व ब्राह्मण धर्मशाला रेवती रेंज मे संपन्न हुआ। जिला सम्मेलन को कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट सांसद शंकर लालवानी राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा विधायक सुश्री उषा ठाकुर जितु जिराती ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने संबोधित किया।

जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जी रामजी बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए जनता के बीच निचे तक पहुंचेगी । सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दो दिन पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण आया था उस सर्वेक्षण मे बताया था कि पूरी दुनिया मे मंदी का माहौल है लेकिन हमारे देश में तेजी से विकास हो रहा है और इस देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जब तक गांव का व्यक्ति हमारा किसान हमारा गरीब व्यक्ति

आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और उसी को लेकर जो पुराना कानून था उसमें बेहतर परिवर्तन करते हुए हमारे मजदूरों को और ज्यादा मजदूरी मिले उसको लेकर एक नया बिल लाया गया जिसे हम पहले मनरेगा बोलते थे अब जी रामजी बोलते हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश के है और ये जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र की मूल आधार है और हम जब सुबह उठते हैं तो राम राम काकाजी राम राम काकी राम राम बा साब राम राम हमारा सम्मान जनक संबोधन है और राम हमारे आराध्य है तो ये दोनों को जोड़ते हुए बहुत ही सोच समझकर इस योजना का नाम जी रामजी रखा ।

शंकराचार्य के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने सद्बुद्धि प्रार्थना पंडरीनाथ मंदिर की

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शंकराचार्य के अपमान के विरोध में काल भैरव मंदिर पंढरीनाथ मंदिर पर झंझ मजीरे बजाकर सद्बुद्धि प्रार्थना सभा की और कहा है कि प्रयागराज के संगम में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुए व्यवहार की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा एक प्रतिष्ठित शंकराचार्य से उनके पद का प्रमाण मांगना धार्मिक परंपराओं और प्रशासनिक मर्यादा का घोर उल्लंघन है। देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि शंकराचार्य पद की मान्यता तय करने का अधिकार विद्वत परिषद और सनातन परंपरा को है, न कि किसी सरकारी अधिकारी को। प्रशासन का दायित्व कानून-व्यवस्था तक सीमित है, न कि धर्मगुरुओं की गरिमा पर सवाल उठाना। उन्होंने कहा कि जो सरकार स्वयं को धर्म की रक्षक बताती है, वही आज शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धार्मिक पद का अपमान कर रही है।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

क्या आर्थिक समीक्षा के सुझावों से कमजोर होगा 'सूचना का अधिकार' कानून?

इस कानून के तहत देश का हर नागरिक सरकारी विभाग और संस्थाओं से उनके कामकाज, योजनाओं एवं उनके प्रभाव, वित्तीय स्थिति तथा नियमों आदि की जानकारी मांग सकता है। कानून ने देश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। यह देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी तंत्र और उसके कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यह कानून सरकार और जनता के बीच सूचना के सेतु के रूप में काम करता है और परस्पर भरोसे का निर्माण करता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दोषियों को कानून के कठघरे में लाने की प्रक्रिया में भी इसकी महती भूमिका है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी इन विशेषताओं में अगर कमी या कटौती की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह कानून कमजोर होगा। यह मसला इसलिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि संसद में हाल में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रपट में आरटीआइ कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है। तर्क दिए गए हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि गोपनीय रपट और मसविदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त की जा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से सूचना के अधिकार की मांग के मद्देनजर वर्ष 2005 इससे संबंधित कानून को लागू किया गया था। इसके तहत देश का हर नागरिक सरकारी विभाग और संस्थाओं से उनके कामकाज, योजनाओं एवं उनके प्रभाव, वित्तीय स्थिति तथा नियमों आदि की जानकारी मांग सकता है। संबंधित अधिकारी तय समय के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होते हैं। मगर समय के साथ सरकारी तंत्र की उदासीनता, लापरवाही और निहित स्वार्थों के कारण जानकारी छिपाने के प्रयासों से इस कानून की प्रभावशीलता में कमी देखी गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में आर्थिक समीक्षा रपट में सूचना के अधिकारों का फिर से अध्ययन करने और कुछ मामलों में छूट हासिल करने की वकालत ने चिंता के स्तर को और बढ़ा दिया है। एक तरफ सरकार जब अपने कामकाज में 'पारदर्शिता लाने' और भ्रष्टाचार को लेकर 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपनाने पर जोर देती हो और दूसरी तरफ सूचना के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाए, तो यह नीति और नीयत के बीच विरोधाभास पैदा करता है।

(2 फरवरी - वेटलैंड दिवस)

'प्रवासी पक्षियों का इंदौर कनेक्ट और प्रदूषण, कब्जे करते डिस्कनेक्ट'

सर्द जाडो के मौसम मे प्रवासी पक्षियों के आगमन की शुरुआत हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर इनका महत्व अब बढ़ चला है। आंद्रभुमि को सहेजना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। देश मे इनकी संधि संख्या लगभग एक सैकडा हो चुकी है। इंदौर शहर के दो प्रक्षेत्र सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को पूर्व से ही यूनेस्को द्वारा रामसर संधि से अधिसूचित किया जा चुका है। पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत वेटलैंड (सरंक्षण एवम प्रबंधन अधिनियम 2017) सरंक्षित व सुरक्षित किये गए है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड मे अन्य गैर वेटलैंड गतिविधियों अथवा उपयोग को अतिक्रमण माना जाता है। उद्योग स्थापना या विस्तार अथवा निर्माण नही किया जा सकता। मलबा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का संग्रहण कचरे का निपटान तथा अवैध शिकार प्रतिबंधित होता है। उ'चतम बाढ़ स्तर से पचास मीटर के भीतर स्थायी निर्माण नही होना चाहिए। उद्योग तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से निकले दूषित जल व अनउपचारित कचरे का निपटान यहाँ पूर्ण प्रतिबंधित होता है। प्रतिवर्ष जाडो के मौसम मे प्रवासी पक्षियों का रामसर साइट पर आगमन होता है। यहाँ सारे नियमो का पालन किया जाना प्रोटोकाल के तहत जरूरी है।। वृहद क्षेत्रफल मे जलकुंभी नही होना चाहिए। मशीनी उपकरण सहित मैदानी अमला व विषय विशेषज्ञों द्वारा इसका निपटान किया जाता है। केंद्र व रा'य सरकार द्वारा वेटलैंड प्राधिकरण के नियम प्रावधान मे है। पर्यावरण विभाग इसका नोडल कार्यालय होता है तथा एपको सेवा प्रदाता है। मध्यप्रदेश के दो प्रमुख शहरों राजधानी भोपाल के बड़े तालाब और व्यावसायिक राजधानी व स्व'छता मे प्रथम शहर इंदौर के यशवंत सागर व सिरपुर तालाब का वेटलैंड की रामसर साइट होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है।

गौरतलब है की सिरपुर मे विचरण करने वाले प्रवासी व भारतीय पक्षियों का विवरण तालाब के पास पट्टीका व बोर्ड पर सचित्र जारी किया गया है। निगम ने विधार्थियो व नागरिको के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध की है।

रामसर कंवेंशन आन वेटलैंड की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डा. मसुंदा मुंबा भी इन स्थानों पर कार्यालयीन भ्रमण कर चुकी है। मूलत: इन स्थानों पर अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायते है, जिनका निराकरण अविलंब होना जरूरी है।

शहर के अन्य तालाबों बिलावली तालाब, पिपल्यापाला, तलावली, लसुड़ीया तालाब , अन्नपूर्णा क्षेत्र(गिट्टी खदान) जवाहर टेकरी और दूसरे जलस्रोत जिनमे कुए , बावड़ीया भी शामिल है इनकी मूल प्रकृति व स्वरूप को बरकरार रखना जरूरी है। पीपल्याहाना कहानी की पुनरावृत्ति न हो।

बात फ्लोरा (वनस्पतिजात) एवम जब फौना (प्राणीजात) की आती है तो निश्चित रूप से अलर्ट तथा एक्शन मोड मे आना बेहद जरूरी हो जाता है।

इंदौर मे जलस्त्रोत और उससे जुड़े पक्षियों के प्रवास और सरंक्षण हेतु वृहद स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।सामाजिक कार्यकर्ता व पर्यावरणविद हमेशा शहर को जागरूक करे इसके पूर्व ही शासन प्रशासन को ये संज्ञान स्वत: लेना चाहिए।

निर्लेश तिवारी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: व्यक्ति निर्माण से विश्व कल्याण की यात्रा

'हम शाखाएं नहीं चलाते, जीवन गढ़ते हैं।' संघ की कार्यपद्धति को व्याख्यायित करने वाला यह सूत्र मात्र एक कथन नहीं, बल्कि उस मौन क्रांति का आधार है जिसने भारत की सामाजिक चेतना को नया आयाम दिया है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) केवल एक संगठन नहीं, अपितु एक विचार, एक अनुशासित आचरण और जीवंत सांस्कृतिक परंपरा बन चुका है। इसकी जड़ें भारत की सनातन मिट्टी में जितनी गहरी हैं, इसका विस्तार विश्व पटल पर उतना ही व्यापक है।

सन् 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा रोपा गया यह बीज किसी तात्कालिक राजनीति की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक 'सांस्कृतिक समाधान' था। डॉ. हेडगेवार का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण है, जब तक समाज आत्मबोध और राष्ट्रप्रेम के सूत्र में न बंधा हो। इसी विजन से 'शाखा' का जन्म हुआ, जहाँ खेल, योग और वैचारिक विमर्श के माध्यम से 'स्वयंसेवक' के रूप में राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व गढ़ा जाता है।

संघ की मूल शक्ति उसकी 'शाखा' है। यह एक ऐसा खुला मंच है जहाँ पद, प्रतिष्ठा या जाति का भेद विलीन हो जाता है। यहाँ नेतृत्व जन्मजात नहीं, बल्कि साधना और समर्पण से अर्जित होता है। 'हिंदुत्व' को एक समावेशी सांस्कृतिक पहचान मानते हुए संघ ने सामाजिक समरसता को व्यवहार में उतारा है। एक ही पंक्ति में भोजन और एक ही गणवेश में प्रशिक्षण, भारत में व्याप्त जातिवाद की जड़ों पर संघ का सबसे प्रखर प्रहार है।

संघ ने कभी प्रचार को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि 'सेवा' को ही संगठन का परिचय बनाया। 'सेवा भारती' और 'वनवासी कल्याण आश्रम' जैसे प्रकल्पों के माध्यम से देश के सुदूर जनजातीय अंचलों और वंचित बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के कार्य किए जा रहे हैं। आपदाओं के समय स्वयंसेवकों की तत्परता यह सिद्ध करती है कि संवेदनशीलता ही राष्ट्र की असली शक्ति है। आज संघ का विचार भौगोलिक सीमाओं को लांघ चुका है। विश्व के अनेक देशों में संघ (हिंदू स्वयंसेवक संघ के रूप में) भारतीय प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ रहा है। संघ की निस्वार्थ सेवा प्रवृत्ति ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड संकट के दौरान 'वसुधैव कुटुम्बकम' के भारतीय दर्शन को वैश्विक मान्यता दिलाई है। यह विस्तार किसी भू-भाग को जीतने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक कल्याण के लिए है।

विविध क्षेत्रों में राष्ट्र-निर्माण की प्रेरणा से उपजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, विज्ञान भारती, साहित्य भारती, सेवा भारती, शिक्षा संस्कृति न्यास , विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेविका समिति,भारतीय मजदूर संघ जैसे अनेकों अनुषांगिक संगठन आज अपने-अपने क्षेत्रों में 'राष्ट्रहित सर्वोपरि' के मंत्र के साथ कार्य कर रहे हैं। ये संगठन प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र होकर भी संघ के उसी एकात्म दर्शन से पोषित हैं, जो समाज को समर्थ और स्वाभिमानी बनाना चाहता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति निर्माण से प्रारंभ होकर विश्व कल्याण तक फैली यह यात्रा वास्तव में भारतीय मानस के पुनरुत्थान की यात्रा है। महत्वपूर्ण यह है कि संघ ने सत्ता को कभी साध्य नहीं माना, बल्कि समाज को इतना सशक्त बनाने का संकल्प लिया कि वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। आज यह विचार एक 'संगठन' की सीमाओं को पार कर जन-जन की 'सामूहिक चेतना' बन चुका है।

लेखक: प्रो. (डॉ.) मनमोहन प्रकाश

आंचलिक

कॉलेज में आपत्तिजनक रील बनाई गई, वायरल होने पर छात्रों का विरोध

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन • भीकनगांव स्थित टंट्या मामा शासकीय महाविद्यालय में एक आपत्तिजनक रील बनाने का मामला सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बाहरी युवकों ने कॉलेज के छात्रों की मदद से कक्षा में बैठकर गाली-गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। जानकारी के अनुसार, यह घटना 23-24 जनवरी की है। कुछ बाहरी युवकों ने कॉलेज के छात्रों की सहायता से कक्षा में छात्रों की बेंच और प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठकर वीडियो रील बनाई थी। इस रील में आपत्तिजनक भाषा का जमकर प्रयोग किया गया है। महाविद्यालय प्रबंधन को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी।

वायरल रील के संबंध में कॉलेज के छात्रों को पता चलने पर उन्होंने शनिवार शाम को आपत्ति दर्ज कराई। छात्रों ने प्राचार्य से शिकायत की और इसमें शामिल छात्रों तथा बाहरी युवकों पर कार्रवाई की मांग की। मामला तूल पकड़ता देख प्राचार्य ने संबंधित छात्रों से माफी मंगवाकर स्थिति को शांत कराया। हालांकि, सरकारी कॉलेज में बाहरी युवकों की एंट्री और आपत्तिजनक रील बनाकर वायरल करने से छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों की शिकायत और सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद भीकनगांव कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है। प्रभारी प्राचार्य लक्ष्मण डाबर ने बताया कि छात्रों की शिकायत के बाद रील बनाने से संबंधित छात्रों को चेतावनी दी गई और उनसे माफी मंगवाई गई है।

अगरबत्ती वाले ने सप्लाई किया पटाखे का सामान, अवैध पटाखा फैक्ट्री केस में मजदूर सप्लायर ने किया खुलासा

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • अवैध पटाखा फैक्ट्री केस में गिरफ्तार हुए आरोपी नवीन यादव ने पुलिस पूछताछ में खुलासे किए हैं। नवीन ने बताया कि वह मजदूरों की सप्लाई करता था, बाकी देवास का जीतू भाटी कच्चे माल की सप्लाई करता था। भाटी ही बारूद और सामान लाकर पटाखे बनवाता था। वहीं कांग्रेस नेता प्रोफेसर इमरान परयानी के पास पटाखों को बेचने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि परयानी के पास बेचने और स्टाक का लाइसेंस हैं। मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी नवीन यादव को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने दो दिन का रिमांड मांगा हैं। टीआई प्रवीण आर्य का कहना है कि, अवैध पटाखा फैक्ट्री केस में आरोपी नवीन यादव का क्लू मिला था। पूर्व में गिरफ्तार हो चुके जब्त पिकअप ड्राइवर

अरबाज खान ने नवीन के बारे में जानकारी दी थी। बैतूल निवासी नवीन यादव को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में बताया कि वह सिर्फ पटाखा बनाने के लिए मजदूरों की व्यवस्था करता था। उसके जिम्मे सिर्फ यहीं काम था। जानकारी मिली है कि, देवास निवासी जीतू भाटी भी इस कारोबार में संलिप्त हैं। जीतू का काम पटाखों के लिए बारूद, रस्सी सहित अन्य सामान को फैक्ट्री तक लाने का था। इसके अलावा इमरान परयानी की मुख्य भूमिका है। परयानी के पास पटाखा बेचने और स्टाक का लाइसेंस हैं, इसलिए अवैध फैक्ट्री में बने पटाखों का वह अपने गोदाम में स्टाक कर कारोबार की फिराक में था। फिलहाल, परयानी जीतू भाटी फरार चल रहे हैं। दोनों की तलाश चल रही हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से करीब दो टन बारूद और रस्सियां मिली हैं। एसपी मनोज कुमार राय ने कहा- अवैध फैक्ट्री सम्यक गोल्ड कॉलोनी के क्लब हाउस की छत पर चलाई जा रही थी। पुलिस जिस वक्त वहां पहुंची, विस्फोटक शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। मौके पर एक पिकअप वाहन खड़ा था। उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है।

मंजू दादू को मिली प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी

दैनिक इंदौर संकेत

बुरहानपुर • प्रदेश भाजपा संगठन ने नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें केंद्रीय बजट 2026 के प्रचार अभियान और जन संवाद कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश स्तरीय टोली का दायित्व दिया गया है।

यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम की सहमति से लिया गया है। यह अभियान 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा।

इस प्रदेश स्तरीय टोली का गठन आम जनमानस और कार्यकर्ताओं के बीच बजट की प्रमुख विशेषताओं के प्रचार-प्रसार और उसके सफल क्रियान्वयन के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बजट में शामिल जनकल्याणकारी प्रावधानों की सही और स्पष्ट जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाना है।

असीरगढ़ किले में दिखा 7 फीट का अजगर, पर्यटकों को रोका गया

दैनिक इंदौर संकेत

बुरहानपुर • असीरगढ़ किले के गेट नंबर 4 पर शनिवार को सात फीट का एक अजगर देखा गया। अजगर दिखने के बाद पर्यटकों को किले में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद नेपानगर के सर्प मित्र एरिक साइमन को बुलाया गया। साइमन ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू किया।

वन विभाग ने मौके पर पंचनामा भी बनाया। अजगर को बाद में सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। किले के सुरक्षा श्रमिक ने सबसे पहले गेट नंबर चार पर अजगर देखा था और वन विभाग की हसनपुरा टीम को इसकी जानकारी दी थी।

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन रक्षक उत्तर हसनपुरा गोविंद महाजन, श्रेयांश सोलंकी और बीट गार्ड रघुराज सिंह सोलंकी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अजगर को हसनपुरा बीट के कक्ष क्रमांक 202 में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया।

कलेक्टर ने दिए 'मरीज के मरने पर क्राउड मैनेजमेंट टिप्स'

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • खंडवा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइंस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान 2014 बैच के आईएएस और खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को क्राउड मैनेजमेंट पर अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मरीज की मौत के बाद अस्पतालों में बनने वाली तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों को पहले से मानसिक और प्रशासनिक तैयारी रखनी चाहिए।

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि जब किसी मरीज की मौत होती है, तो सबसे पहले डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगते हैं। इसके बाद आक्रोशित भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो जाती है। इस भीड़ में एक व्यक्ति आपसे बात करता है, लेकिन वह उस समय लॉजिक से नहीं सोचता।

उन्होंने कहा कि सामने खड़ा व्यक्ति मरीज का परिजन होता है, उसके साथ भीड़ भी होती है। ऐसे में डॉक्टरों को पहले उसकी मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा। वह भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है, इसलिए उसे सिर्फ तर्क से नहीं समझाया जा सकता। कलेक्टर ने बताया कि अक्सर डॉक्टर वहीं भाषा भीड़ से बोलने लगते हैं, जो वे आपस में बोलते हैं। मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करने से भीड़ को लगता है कि डॉक्टर उसे अनपढ़ समझ रहा है, जिससे गुस्सा और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीड़ से कहते हैं कि मरीज को फलां बीमारी थी, हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन हर जगह और हर समय टेक्निकल भाषा नहीं चलती। ऐसे समय में लोगों के इमोशन हावी होते हैं और उन्हें संवेदनशील तरीके से समझाना जरूरी होता है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि अगर मरीज की हालत गंभीर है और मौत की आशंका है, तो पहले से तैयारी रखें। लोकल मजिस्ट्रेट और पुलिस के नंबर डॉक्टरों के पास होने चाहिए और समय रहते उन्हें सूचना देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोचते हैं कि रिकॉर्ड दिखाकर सब समझा देंगे, लेकिन भीड़ रिकॉर्ड देखने नहीं आती।

मोरटक्का में नर्मदा ओवरब्रिज पर डामरीकरण शुरू फरवरी के आखिरी सप्ताह से टू-लेन पर शुरू होगा ट्रैफिक

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा • मोरटक्का में नर्मदा नदी पर बन रहे नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य ने आखिरकार निर्णायक मोड़ ले लिया है। पुल पर डामरीकरण (डामर बिछाने) का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह वही ओवरब्रिज है, जिसके निर्माण में हो रही देरी और धीमी प्रगति को लेकर दैनिक भास्कर ने पहले कई बार मुद्दा उठाया था। इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। खंडवा एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष सोनी के मुताबिक, यदि मौसम और तकनीकी प्रक्रिया अनुकूल रही तो फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में ओवरब्रिज के टू-लेन वाले हिस्से से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। ओवरब्रिज का कार्य समय-सीमा से काफी पीछे चल रहा है, जिससे इंदौर-खंडवा नेशनल हाईवे पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही थी। अधूरे निर्माण के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई थी। अब निर्माण एजेंसी और एनएचएआई के द्वारा कार्य में तेजी लाई गई। डामरीकरण के बाद पुल पर क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड और सेफ्टी ऑडिट जैसे कार्य किए जाएंगे। दो लेन शुरू होने से भारी वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलेगी। ओवरब्रिज चालू होने से खंडवा से इंदौर और बुरहानपुर सहित दक्षिण राज्यों का सफर और आसान होगा। नर्मदा पुल पर लगने वाले जाम और समय की बर्बादी से भी लोगों को निजात मिलेगी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026

अल्काराज ने रचा इतिहास, जोकोविच का 25वें ग्रैंड स्लैम का सपना तोड़ा

मेलबर्न (एजेंसी) ● दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को चार सेटों में रविवार को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया और 22 साल की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अल्काराज ओपन युग में सभी चार प्रमुख खिताब कम से कम एक बार जीतने वाले सिर्फ़ छठे व्यक्ति हैं, जो रॉड लेवर, आंद्रे अगासी, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच के साथ शामिल हो गए हैं। यह एक ऐसा कारनामा है जिसे इस स्पेनिश खिलाड़ी ने खुले तौर पर अपने सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक के रूप में अपनाया है, एक ऐसी उपलब्धि जो अब उनके युवा करियर की सबसे बड़ी जीत के रूप में चमक रही है।

एक अजीब तरह से फ्लैट शुरुआती सेट के बाद, जिसमें जोकोविच ने ज़ोरदार शुरुआत की, अल्काराज ने बेसलाइन से लॉक इन किया और अपने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन फ़ाइनल पर कब्ज़ा कर लिया। स्पेन के इस खिलाड़ी ने दूसरे सेट में अपने विरोधी की सर्विस दो बार तोड़ी और तीसरे सेट में कई शानदार ऑल-कोर्ट एक्सचेंज के साथ अपने सबसे अच्छे फॉर्म में दिखे। जोकोविच ने चौथे सेट में अपने खास अंदाज में ज़ोर लगाया, दूसरे गेम में छह ब्रेक पॉइंट बचाए। लेकिन 38 साल के जोकोविच रॉड लेवर एरिना पर अपने परफेक्ट चैंपियनशिप-मैच रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाए और उसे बनाए नहीं रख पाए। अल्काराज ने चौथे सेट के 12वें गेम में निर्णायक ब्रेक लेकर तीन घंटे, दो मिनट की जीत पक्की की और यह पक्का किया कि जोकोविच का ऑल-टाइम रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम टाइटल का इंतज़ार जारी रहे। अल्काराज अब सात बार के ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन हैं, जिससे वह ऑल-टाइम लिस्ट में अपने साथी एटीपी नंबर 1 क्लब के सदस्य जॉन मैकेनरो और मैट्स विलेंडर के बराबर आ गए हैं। स्पैनियार्ड की मेलबर्न जीत के साथ, अल्काराज और उनके बड़े प्रतिद्वंद्वी जैनिक सिनर ने अब मिलकर पिछले नौ ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जो 2023 यूएस ओपन में जोकोविच की जीत से शुरू हुए थे। अल्काराज और जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार दूसरे साल भिड़े, जब जोकोविच ने 2025 के क्वार्टर-फ़ाइनल में स्पैनियार्ड को चार सेट में हराया था। रविवार की जीत के साथ, अल्काराज ने दोनों की हेड2हेड सीरीज को 5-5 से बराबर कर दिया, और अब उन्होंने जोकोविच के ख़िलाफ खेले गए अपने तीनों बड़े टाइटल मैच जीत लिए हैं।

सिनर के खिलाफ की तरह ही, जोकोविच अपने फोरहैंड से खेल को कंट्रोल करने के लिए तैयार थे, और सर्बियाई खिलाड़ी ने चौथे गेम में सेट के शुरुआती तीन ब्रेक पॉइंट हासिल किए। हालांकि अल्काराज ने पहले दो ब्रेक पॉइंट को रोकने के लिए हिम्मत दिखाई, लेकिन जोकोविच ने तीसरे सेट में एक लंबी बेसलाइन रैली में जीत हासिल करके शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। अल्काराज़ ने खुद शुक्रवार को अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के खिलाफ़ टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे लंबा सेमी-फ़ाइनल खेला, और उन्होंने शुरुआती सेट में अपनी आम हाई एनर्जी नहीं दिखाई। जोकोविच ने आठवें गेम में फिर से अपने विरोधी की सर्विस तोड़कर अपने मोमेंटम का फ़ायदा उठाया और एक सेट जीत लिया, जिसमें वह सर्विस से सिर्फ़ दो पॉइंट पीछे रह गए।

अर्शदीप टी20 में सबसे अधिक रन देकर पांच विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी) ●तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पांच विकेटों की सहायता से भारतीय क्रिकेट टीम ने पांचवे और अंतिम टी20 में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने ये सीरीज 4-1 से जीती पर मैच में पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसे वह याद नहीं रखना चाहेंगे। अर्शदीप इसी के साथ ही किसी अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबले में सबसे ज्यादा रन देकर 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ के नाम दर्ज था। जोसेफ ने जोहानसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2023 में 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एंगिडी ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में 39 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2026 में लाइव परफॉर्मेंस से समां बांधेंगी मोनाली ठाकुर

मुंबई (एजेंसी) ● गायिका मोनाली ठाकुर दक्षिण मुंबई में आयोजित होने वाले काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2026 में लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह रविवार, 8 फरवरी को इस नौ दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के तहत प्रस्तुति देंगी। मुंबई के सबसे चर्चित शीतकालीन आयोजनों में से एक यह फेस्टिवल 31 जनवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। इसमें काला घोड़ा क्षेत्र में संगीत, कला, नृत्य, रंगमंच और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक देखने को मिलेगी। मोनाली ठाकुर की परफॉर्मेंस एशियाटिक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर होगी, जहां वह अपनी मधुर ग़ज़लों और ऊर्जावान हिट गानों का शानदार मिश्रण पेश करेंगी, जो एक गायिका के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विकास से जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा, 'मोनाली का मुंबई और यहां की लाइव म्यूज़िक संस्कृति से हमेशा खास जुड़ाव रहा है। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में उनकी प्रस्तुति उनके सबसे पसंदीदा बॉलीवुड हिट गानों और आत्मा को छू लेने वाली धुनों का संगम होगी। वह इस परफॉर्मेंस को दर्शकों के लिए यादगार बनाना चाहती हैं।

'हेरा फेरी 3' बंद नहीं हुई, यह जरूर बनेगी: परेश रावल

मुंबई (एजेंसी) ● फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अभिनेता परेश रावल ने चुप्पी तोड़ते हुए साफ कर दिया है कि फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कंफर्म किया है कि 'हेरा फेरी 3' बंद नहीं हुई है और यह फिल्म जरूर बनेगी। एक इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा कि फिल्म को लेकर जो भी अफवाहें उड़ रही हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट में देरी उनके कारण नहीं हुई है। परेश रावल के मुताबिक, फिल्म के अटकने की असली वजह अक्षय कुमार और मेकर्स के बीच कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। उन्होंने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार ने उन पर 25 करोड़ रुपये का केस कर दिया है। परेश रावल ने इन दावों को पूरी तरह बकवास बताते हुए कहा कि ऐसी बातें सिर्फ हवा में फैलाई जा रही हैं।

उज्जैन संभाग

बढ़े क्षेत्रफल पर संपत्ति कर वसूलेगा निगम; बकायादारों पर तालाबंदी

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●नगर निगम अब शहर में बढ़े हुए क्षेत्रफल पर संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हॉल और मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी नाप में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल पाया जाएगा, वहां अनिवार्य रूप से संपत्ति कर वसूला जाएगा। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह और उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल ने संपत्ति कर विभाग को वसूली प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के बड़े होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मकानों और सिनेमा हॉल सहित अन्य संपत्तियों की दोबारा नाप की जाए। जो अतिरिक्त निर्माण या बढ़ा हुआ क्षेत्रफल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उसे दर्ज कर नए बिल जारी किए जाएं।

अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि संपत्ति कर के बड़े बकायादारों से सीधे संपर्क कर बकाया राशि वसूली जाए। जिन संपत्ति स्वामियों द्वारा लगातार कर जमा नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ तालाबंदी और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में कई स्थानों पर घरेलू संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसे मामलों में संबंधित उपभोक्ताओं से वाणिज्यिक दर से संपत्ति कर वसूला जाएगा। बैठक में ट्रेड लाइसेंस की भी समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का फील्ड सर्वे कर अनिवार्य रूप से ट्रेड लाइसेंस बनाए जाएं। इसके लिए ट्रेड लाइसेंस का अमला मैदान में उतरकर दुकानों का सर्वे करेगा।

कोरियन कंपनी उज्जैन में बनाएगी यूरीन-किट, कैंसर की जांच होगी

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● शहर के मेडिकल डिवाइस पार्क में दक्षिण कोरिया की कंपनी ई-फाइबर ग्रुप अपनी यूनिट लगाएगी। इस प्रोजेक्ट में 209 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। कंपनी यूनिट के लिए सर्वे कर रही है। निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने की संभावना है। अगले साल से उत्पादन शुरू हो सकता है।

यह प्रदेश की पहली यूनिट होगी, जहां कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए यूरीन आधारित डायग्नोस्टिक किट्स तैयार की जाएंगी। अब तक कैंसर की जांच के लिए महंगी बायोप्सी और जटिल टेस्ट की जरूरत होती थी। नई तकनीक से जांच आसान, तेज और सस्ती होगी। किट्स में नैनो फाइबर और बायो-पॉलीमर का उपयोग होगा। इससे कैंसर की शुरुआती स्टेज में पहचान और रोकथाम संभव होगी। कंपनी हर महीने 50 लाख डायग्नोस्टिक किट्स और 1 करोड़ संबंधित उत्पाद तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस पहल से सामान्य जनता को लाभ मिलेगा। मरीज कम खर्च में सुरक्षित और सरल तरीके से कैंसर की जांच करवा सकेंगे। साथ ही इस यूनिट से तैयार होने वाली किट्स प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में निर्यात भी की जाएगी, जिससे उज्जैन की औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवाओं में नई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनेगी।

साथ ही यूनिट स्थापित होने से रोजगार बढ़ेगा और देश-विदेश के विशेषज्ञ काम के लिए शहर की और रूख कर सकेंगे। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि ई-फाइबर ग्रुप का यह निवेश न केवल प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि उज्जैन को औद्योगिक और स्वास्थ्य हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। विक्रम उद्योगपुरी में कैंसर के उपचार के लिए भी बन रहे रेडियो आइसोटोप: कैंसर के ही उपचार के लिए विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया का पहला मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्लांट शुरू किया है। प्लांट कैंसर, हृदय और दिमाग की बीमारियों की जांच में काम आने वाले रेडियो आइसोटोप तैयार करेगा। आइसोटोप एक विशेष प्रकार का रेडियो तत्व है, जिसे बहुत कम मात्रा में मरीज को इंजेक्शन के रूप में देते हैं। यह इंजेक्शन दर्द रहित होकर कुछ ही मिनट में शरीर में पहुंचता है। इससे पहचान होने के बाद इलाज करते हैं।

सिंहस्थ के पहले संचालन की तैयारी, उज्जैन में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा। अब तक यहां छोटे एटीआर-72 विमान के हिसाब से निर्माण करवाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन हाल ही में जिला प्रशासन ने शासन को रिवाइज प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद हैं कि इसे जल्द स्वीकृति मिलेगी और काम शुरू होगा। दावा किया जा रहा है कि सिंहस्थ के पूर्व एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकेगा।

सिंहस्थ की तैयारियों की कड़ी में उज्जैन-देवास मार्ग स्थित दताना-मताना की हवाई पट्टी को सरकार एयरपोर्ट के रूप में डेवलप कर रही हैं। वर्ष 2025 को 1 नवंबर को मप्र के स्थापना दिवस पर मप्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एयरपोर्ट निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद से प्रक्रियाओं में तेजी आई। निर्माण स्थल पर मिट्टी परीक्षण हुआ। अब तक यहां छोटे एटीआर-72 श्रेणी के विमानों के ?संचालन के प्रबंधन के हिसाब से निर्माण की प्लानिंग थी, लेकिन अब ये और भी विस्तारित हो गई है। जिला प्रशासन ने हाल ही में शासन को यहां बोइंग सी-20 के संचालन के हिसाब रिवाइज प्रस्ताव भेजा है।

अब यह होगा संशोधन अधिग्रहण : अब तक 241 एकड़ जमीन की जरूरत थी, अब दायरा बढ़कर 300 एकड़ से अधिक तक पहुंच सकता है। सर्वे टीम इसके बारे में बताएगी। रन-वे दोगुना होगा : अब तक रन-वे को 1800 मीटर किया जा रहा था, अब रन-वे 3600 मीटर में बनेगा। आसपास सहित 4100 मीटर जमीन चाहिएगी। लागत : अभी तक केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 45 करोड़ की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की थी। अब ये लागत और भी बढ़ जाएगी।

एडीजी उमेश जोगा परिवहन आयुक्त बने, संचालक खेल राकेश गुप्ता को जोन की कमान

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● मध्यप्रदेश गृह विभाग ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। गुरुवार को जारी तबादला आदेश के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन उमेश जोगा का तबादला कर दिया गया है। शासन ने उन्हें परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। जबकि उज्जैन जोन का दायित्व राकेश गुप्ता को सौंपा है, वह संचालक खेल एवं युवक कल्याण हैं। राकेश गुप्ता का इंदौर में लंबा और प्रभावी कार्यकाल रहा है। वे इंदौर रेंज के आईजी, इंदौर के एसएसपी और बाद में शहर के तीसरे पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जब तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर प्रतिनियुक्ति पर गए थे, तब राकेश गुप्ता को इंदौर का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। इंदौर में डीआईजी रहते हुए राकेश गुप्ता ने शहर की कुख्यात सियागंज खड़ी कराई गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसके नेटवर्क को तोड़ा था। इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र में हुए बोहरा व्यापारी हत्याकांड को कुछ ही घंटों में सुलझाया था। इसके अलावा, डॉक्टर के बेटे के अपहरण और हत्याकांड जैसे हाई-प्रोफाइल मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

त्रिनेत्रधारी भगवान महाकाल का रजतचंद्र-त्रिपुण्ड और आभूषण अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट सोमवार तड़के (चार बजे) खुलते ही पंडे-पुजारियों द्वारा गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शकर और फलों के रस से बने पंचामृत से विशेष पूजन संपन्न हुआ। पूजन के दौरान त्रिनेत्रधारी भगवान महाकाल को रजत चंद्र, त्रिपुंड और आभूषण अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। मंदिर में प्रवेश के साथ ही मंत्रोच्चार और 'हरिओम' के जल अर्पण से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कपूर आरती के बाद भगवान के मस्तक पर भांग, चंदन और त्रिपुंड अर्पित कर श्रृंगार पूर्ण किया गया। श्रृंगार के बाद ज्योतिर्लिंग को वस्त्र से ढांककर परंपरानुसार भस्म रमाई गई। भस्म अर्पण के बाद शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल, रुद्राक्ष की माला तथा सुगंधित पुष्पों से बनी मालाएं अर्पित की गईं। मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्प धारण कर भगवान महाकाल अलौकिक रूप में विराजमान हुए। भस्म आरती में फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महा निर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। मान्यता है कि भस्म अर्पण के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

न्यूज ब्रीफ

भागीरथपुरा में दूषित पानी से 32 वीं मौत

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में दूषित पानी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक महीना बीत जाने के बाद भी यहां मौतों का सिलसिला जारी है। रविवार को बस्ती में 32वीं मौत दर्ज की गई, जिसने इलाके में दहशत और बढ़ा दी है। ताज़ा मामला 65 वर्षीय अनिता कुशवाह का है, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अनिता को कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। शुरुआत में इसे सामान्य संक्रमण माना जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया।

धावक को दिल का दौरा, पीछे दौड़ रहे डॉक्टर ने दिया सीपीआर, लेकिन नहीं बची जान

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में रविवार सुबह मैराथन में भाग लेने कोलकाता से आए एक धावक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। फिनिश लाइन से 100 मीटर पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। पीछे दौड़ रहे डॉक्टर ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन धावक की मौत हो गई। धावक की पहचान उनकी टीशर्ट पर लगे बैच से हुई। उनका नाम आर्यन तोड़ी है। वे मूलत: कोलकाता के थे और उन्होंने मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। आर्यन के सीने में अचानक दर्द उठा और वे नीचे बैठ गए। पीछे दौड़ रहे डॉक्टर भरत रावत ने दौड़ पूरी करने के बजाय आर्यन की जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने आर्यन को सीपीआर दिया।

तीन साल में कैसे भरेंगे आरक्षकों के 25 हजार खाली पद

हर साल 7500 आरक्षकों की भर्ती करने का सरकार ने तय किया लक्ष्य

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मप्र में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से पुलिस बल की कमी है। इस कमी की भरपाई करने की मांग लगातार उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि वर्तमान में तय अमले में भी पुलिस आरक्षकों के 25 हजार पद खाली पड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर साल 7500 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस मान से सरकार के इस बार के बचे 3 साल में 22,500 पद ही भर पाएंगे। ऐसे में 3 साल में आरक्षकों के खाली पदों को भरना आसान नहीं है।

बता दें, प्रदेश में पुलिस का स्वीकृत बल एक लाख 26 हजार है। नया थाना खुलने पर ही बल बढ़ता है। रिक्त पदों को भरने में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में एक समय में 7500 से अधिक पुलिस आरक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण नौ माह चलता है। यानी, प्रति वर्ष लगभग 7500 आरक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे अधिक आरक्षकों की भर्ती के पहले प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ानी होगी। हालांकि जबलपुर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। उधर, पुलिसकर्मियों की कमी के कारण, अपराधों की विवेचना और गुणवत्ता प्रभावित होती है, वहीं कोर्ट में चालान प्रस्तुत करने में देरी हो रही है। लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत पंजीबद्ध होने के बाद अपराध दर्ज होने में डेढ़ से दो

साल लग रहे हैं। इसी तरह अपराध पंजीबद्ध होने के बाद अभियोजन में भी अधिकतर मामलों में औसतन दो वर्ष लग रहे हैं।

सरकार की राह में कई बाधाएं - गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने घोषणा की है कि तीन वर्ष तक हर साल 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे रिक्त पदों की पूर्ति की जा सके। इनमें पहला बैच इसी वर्ष अप्रैल-मई तक मिल जाएगा। सच्चाई यह है कि रिक्त पदों को भरने में कम से कम पांच वर्ष लग जाएंगे। कारण, भर्ती के बाद भी पुलिस बल की संख्या प्रति वर्ष तीन से चार हजार ही बढ़ पा रही है। इसका कारण यह कि ओबीसी आरक्षण के चलते 13 प्रतिशत पद होल्ड किए जाने के बाद 6,525 पदों के विरुद्ध ही अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। इसमें लगभग एक हजार ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्यों में या केंद्र में अच्छी नौकरी मिलने पर ज्वाइन नहीं करते हैं। उधर, 62 वर्ष की सेवा पूरी कर लगभग डेढ़ हजार पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में हर साल लगभग चार हजार बल ही बढ़ रहा है। उधर, जनसंख्या और अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

मप्र में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा

मप्र में पुलिस का अमला पर्याप्त नहीं होने के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो मध्य प्रदेश गंभीर अपराधों की सर्वाधिक संख्या के मामले में पहले से पांचवें नंबर के बीच में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध (22,323 मामले) मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में राज्य देश में पांचवें नंबर पर है। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2025 में 600 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी हो गई। साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें पांच लाख से ऊपर रहीं। इसके बाद भी स्थिति यह है कि प्रदेश भर में साइबर का कुल पुलिस बल 300 भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में एक झटके में 60 हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती की। 32 हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अपराध पांच लाख के करीब होने के बाद भी एक लाख पुलिसकर्मी ही हैं। इनमें भी लगभग 10 प्रतिशत अवकाश पर रहते हैं।

सीएचएल केयर अस्पताल के पंजीयन निरस्त करने का नोटिस, मरीज भर्ती के बाद भी कर रहे काम

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर के बड़े निजी अस्पताल में शामिल केयर ष्ट।रु को आखिर पंजीयन निरस्ती का नोटिस जारी हो गया है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने यह नोटिस संचालक को दे दिया है। इसकी वजह यह है कि अस्पताल में मरीजों के भर्ती रहने के दौरान भी गैरकानूनी तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसके चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। द सूत्र ने यह मुद्दा उठाया था।

यह दिया गया है नोटिस

ष्ट्रू।ह्र डॉक्टर माधव हसानी ने यह नोटिस अस्पताल संचालक को दिया है। इसमें कहा गया है कि आपके परिसर में अनधिकृत अतिक्रमण करने

की शिकायतें मिली है। इसके लिए आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया था।

इस पर 19 दिसंबर को आपके द्वारा जवाब देने के लिए 15 दिन का समय चाहा गया था। लेकिन आज दिनांक तक जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही अभी भी लगातार काम किया जा रहा है। यह काम भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के विपरीत होकर उनके जीवन से खिलवाड़ है।

क्यों न पंजीयन निरस्त किया जाए-ष्ट्रू।ह्र के नोटिस में कहा गया है कि यह अंतिम चेतावनी दी जाती है। यदि भविष्य में भी आदेशों की अवहेलना की जाती है और मरीजों के भर्ती रहने के दौरान निर्माण कार्य जारी रहता है, तो कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल रजिस्ट्रेशन एक्ट की धाराओं के तहत पंजीयन निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।

लगातार नियमों को ताक पर रख रहा अस्पताल-अस्पताल बीते एक महीने से मध्यप्रदेश शासन के नियमों, आदेशों और नोटिस को ताक पर रख रहा है। आयुष्मान योजना में मरीजों से राशि लेने के चलते एक-दो नहीं पूरे तीन नोटिस एक महीने में प्रबंधन को जारी हो चुके हैं। वहीं अस्पताल द्वारा रेडक्रास सोसायटी से भी राशि लेने की कोशिश की गई, जिस पर भी नोटिस जारी हुए।

निगम में खुली रिश्वत, एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा ने फरियादी से करवाया स्टिंग ऑपरेशन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर नगर निगम में 150 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला हो चुका है, लेकिन रिश्वत का खेल जारी है। अब इस मामले में एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा उर्फ मामा ने फरियादी से ही स्टिंग ऑपरेशन करवाते हुए वीडियो बनवा लिया। इसमें 400 रुपए की रिश्वत की मांग थी।

इस काम के लिए मांगी गई थी रिश्वत-यह मामला शनिवार 31 जनवरी का है। एक फरियादी महिला आकांक्षा पाल से मनीष शर्मा को जानकारी मिली की केवाईसी अपडेट और आईडी रिकवर के लिए 400 रुपए मांगे गए हैं। इसके बाद स्टिंग बनाने की योजना बनी और फिर फरियादी ने रिश्वत मांगने वाली निगम कर्मचारी पिंकी को फोन किया।

मिलने की जगह तय हुई और उन्हें निगम के गेट पर बुलाया गया। मनीष फरियादी को अपनी कार में लेकर गए और पूरी बात भी रिकार्ड करते रहे।

गेट पर आई युवती बनाया वीडियो-गेट पर युवती आई, तब वहां पहले से ही मनीष शर्मा द्वारा तैनात किए गए युवकों ने वीडियो बनाया। इसमें फरियादी से 400 रुपए की मांग की गई। ऑनलाइन ही राशि दी गई। इसमें फरियादी ने कहा भी कि यह काम तो बिना रुपए के हो जाता है। अब आप मेरा काम जल्दी कर देना, इसके रुपए नहीं लगते हैं। वीडियो में फिर नजर आता है कि मनीष मामा आते हैं और कर्मचारी से रिश्वत मांगने को लेकर सफाई मांगते हैं।

करेंगे औपचारिक शिकायत होगी जांच-रविवार एक फरवरी होने के चलते इस मामले की अभी औपचारिक शिकायत नहीं हुई है। एमआईसी मेंबर ने बताया कि इसमें सोमवार को औपचारिक शिकायत की जाएगी और जांच होगी। साथ ही कार्रवाई की जाएगी।

मोदी सरकार का बजट छल और छलावों से भरा-कांग्रेस

केंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश को कुछ हासिल नहीं, यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाएगा- अमित चौरसिया

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के नाम पर सिर्फ भ्रम पैदा करने वाला दस्तावेज़ है। मुख्यमंत्री द्वारा इसे जनहितैषी बताना ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। आज देश बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला असुरक्षा और विफल नीतियों से जूझ रहा है, लेकिन बजट इन मूल समस्याओं से आंखें मूंदे हुए है।

प्रदेश में एक लाख से अधिक सरकारी पद वर्षों से खाली हैं, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और आरक्षण में प्रमोशन जैसे संवैधानिक अधिकार लंबित हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। किसानों को अन्नदाता कहा जा रहा है, जबकि MSP की गारंटी नहीं, फसल बीमा में भारी गड़बड़ियां हैं और मक्का, मूंग, आलू, प्याज, लहसुन जैसी फसलों में किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

बढ़ती महिला असुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की असल तस्वीर इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की घटना से सामने आ चुकी है, जहाँ NICU में चूहों ने नवजात बच्चों को काटा। यह सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता प्रमाण है। यह बजट राहत नहीं, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास है, जिसका कांग्रेस पुरज़ोर विरोध करती है।

दूषित पानी छोड़ रहे उद्योगों पर की जाए सख्त कार्यवाही करें-मंत्री सिलावट

फैक्ट्री के दूषित पानी को नाले में छोड़ रहे थे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● जिले की सांवेर तहसील के ग्राम कुमेडी और भांग्या क्षेत्र में उद्योगों द्वारा दूषित पानी खेतों और खाली जमीन और नालों में छोड़ने का मामला संज्ञान में आने पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने आयुक्त नगर निगम इन्दौर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण को भी अवगत कराया। मंत्री सिलावट ने दूषित जल छोड़ने वाली फैक्ट्री के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने तत्काल मौके पर कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी निधि वर्मा एवं प्रशासनिक टीम को भेजा। आयुक्त द्वारा भी जोन अधिकारी एवं सीएआई सहित निगम अमले को भेजा गया।

20 हजार का स्पॉट फाईन-मौका निरीक्षण पर पाया गया कि नाले के पास डिलाईट इनोवेशन नामक फैक्टरी का आउटलेट चोक है। इनके द्वारा कचरा नाले में फेंका जा रहा और गंदा पानी नाले में छोड़ा जा रहा है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी निधि वर्मा एवं नगर निगम की प्रशासनिक टीम द्वारा सख्त हिदायत दी जाकर 20 हजार रुपये का स्पॉट फाईन किया गया। सिलावट ने बताया कि सांवेर तहसील के ग्राम कुमेडी और भांग्या सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा दूषित पानी खेतों और खाली जमीन और नालों में छोड़ने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मेट्रो स्टेशन के लिए तोड़ी मल्टीलेवल पार्किंग

एमजी रोड पर मेट्रो स्टेशन के लिए मल्टीलेवल पार्किंग को तोड़ती हुई जेसीबी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा एमजी रोड पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन के प्रवेश मार्ग में शिवाजी मार्केट की मल्टीलेवल पार्किंग बाधक बन रही थी। कॉर्पोरेशन ने नगर निगम से इस पार्किंग की जमीन मांगी थी। पिछली एमआईसी बैठक में नगर निगम ने पार्किंग की जमीन मेट्रो को देने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद बीते दो दिनों से पार्किंग तोड़ने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दो करोड़ रुपए निगम को दिए हैं। सुरक्षा को देखते हुए रात के समय में पार्किंग तोड़ने का काम किया जा रहा है। नगर निगम ने यह पार्किंग वर्ष 2010 में जेएनयूआरएम योजना के तहत सड़क पर होने वाली पार्किंग समस्या को खत्म करने के लिए बनाई थी। एमजी रोड पर मेट्रो का मुख्य स्टेशन अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। शिवाजी मार्केट पार्किंग से होकर ही मेट्रो स्टेशन का प्रवेश मार्ग बनाया जाएगा।

घोटाला वार्ड 74 में भी बड़े पैमाने पर सर्वे में मिली थी गड़बड़ी, पूर्व आयुक्त बनाई थी 3 सदस्यीय जांच कमेटी

नगर निगम का संपत्ति कर में घोटाला उजागर, रिपोर्ट में होगा खुलासा!

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर नगर निगम में अब टैक्स घोटाला सामने आया है। इसमें निगम के कुछ अधिकारियों ने 714 मामलों में टैक्स की राशि ही आला अधिकारियों की मंजूरी के बगैर कम कर दी। इसके साथ ही 174 मामलों में संपत्ति के क्षेत्र को कम कर संबंधित व्यक्ति को उपकृत करने का खेल खेला गया।

पूर्व निगम आयुक्त दिलीपकुमार यादव को संपत्ति खातों में किए जा रहे खेल की भनक लग गई थी। इसके चलते उन्होंने 13 अक्टूबर को जांच के आदेश दिए थे। नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त किए बगैर ही अपने स्तर पर विभिन्न संपत्तियों का बकाया टैक्स कम कर दिया गया। साथ ही कई संपत्ति कर के खातों में संपत्ति का क्षेत्रफल भी कम कर दिया गया है। आयुक्त के निर्देश के बाद पूरे मामले की छानबीन के लिए जांच तीन सदस्यीय कमेटी अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, अर्थ जैन, राजस्व विभाग अधीक्षक मनीष जैन की बनाई गई थी। जांच कमेटी ने जांच शुरू की, तो यह बात सामने आई कि इसके लिए नगर पालिका का पोर्टल खंगालना होगा। इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे को जानकारी दी। इस पर उन्होंने तत्काल इस तरह की सारी जानकारी पोर्टल से निकालकर इंदौर नगर निगम को उपलब्ध कराने के आदेश दिए। ई-नगर पालिका पोर्टल से निकलकर जो जानकारी सामने आई है उसने नगर निगम के करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल से इंदौर नगर निगम को मिली जानकारी के अनुसार जिन 714 खातों में बकाया टैक्स की रकम कम की गई है उनमें सबसे ज्यादा 221 मामलों में नगर निगम मुख्यालय से ही यह रकम कम करने का

काम हुआ है। इसके अलावा जोनल कार्यालय के क्षेत्र में देखें तो जोन क्रमांक 22 में सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा 82, जोन क्रमांक 10 के एआरओ द्वारा 48 संपत्ति कर खाते में बकाया राशि को कम किया गया। इसके अतिरिक्त जोनल कार्यालय क्रमांक 3 के सहायक राजस्व अधिकारी ने 36, जोन क्रमांक 8 के ने 27, जोन क्रमांक 17 के ने 23, जोन क्रमांक 7 के और 18 के ने 22-22 संपत्ति कर खाते में बकाया राशि को कम किया। पूरे शहर में 174 संपत्ति कर खाते में संपत्ति के क्षेत्रफल को कम करने का काम किया गया। इसमें सबसे ज्यादा यह काम जोन क्रमांक 22 में, इसके बाद जोन क्रमांक 21 के सहायक राजस्व अधिकारी ने 14, जोन क्रमांक 3 के सहायक राजस्व अधिकारी ने 11, जोन क्रमांक 4 के और 17 के सहायक राजस्व अधिकारी ने 10-10 संपत्ति करके खाते में क्षेत्रफल को कम करने का काम किया। भोपाल से नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यह पूरी रिपोर्ट इंदौर नगर निगम को भेज दी गई है। निगम के पास यह रिपोर्ट आने के बाद अब इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

गड़बड़ी के चलते अतुल रावत पर गिर चुकी है गाज

निगम को जोन 13 वार्ड क्रमांक 74 में स्थित परिसंपत्तियों का अन्य जोनल कार्यालय के राजस्व अमले के माध्यम से वार्ड में दर्ज कुल 11301 संपत्तियों में से 53-9 संपत्तियों का सर्वे कराया गया। इसमें से 2415 संपत्तियों के क्षेत्रफल एवं उपयोग प्रायोजन में अंतर की स्थिति मिली। साथ ही सैकड़ों ऐसी नवीन अपंजीकृत संपत्तियां भी मिली है, जिनके संपत्तिकर खाते निगम कम्प्यूटर रिकार्ड में दर्ज नहीं। अर्थात इनका संपत्तिकर जमा नहीं कराया गया है। सर्वे में पाई गई उक्त संपत्तियों की अनुमानित मांग राशि 6 करोड़ 74 लाख 54 हजार 96 रुपए के लगभग है। अतुल रावत, राजस्व निरीक्षक निगर पालिक निगम, इंदौर में पदस्थ रहने के दौरान जोन क्रमांक 13 में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी का दायित्व सौंपा था। श्री रावत जोन 13 में 4 माह तक पदस्थ रहे। 13 जून 25 को उनका स्थानांतरण नगर परिषद लहार जिला भिंड में किया गया। जब श्री रावत इंदौर में नगर निगम में पदस्थ थे, तो वार्ड क्रमांक 74 में समस्त संपत्तियों के क्षेत्रफल एवं वास्तविक उपयोग तथा प्रायोजन की जांच नियमानुसार किए जाने था। ऐसा न किए जाने के कारण निगम को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हुए है। इसके चलते उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिय गया है। निलंबन के ट्रेविंग ग्राउंड में सेवा देंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।